

**“डोनाल्ड ट्रम्प की तालिबान शांति वार्ता बंद करने से भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा।”**

यह शायद सबसे अच्छा है कि अमेरिकी तालिबान वार्ता इस महीने की शुरुआत में ही रद्द हो गया। तालिबान नेतृत्व के संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप डेविड में प्रस्तावित दौरे से इस क्षेत्र और उससे आगे के निहितार्थों के साथ महत्वपूर्ण भूराजनीतिक परिवर्तन जुड़े थे।

शायद तालिबान बहुत अधिक लालची और अधीर हो गया था या कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति विशेष रूप से वार्ता से प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट नहीं थे और न ही अमेरिकी प्रतिष्ठान इस सौदे से बहुत खुश थे। इस सौदे के बारे में गलतफहमी थी कि अफगानिस्तान में मुख्य अमेरिकी वार्ताकार, जैलमे खालिलजाद, तालिबान के साथ कोई समझौता करने वाला था।

## शुरुआत से

विगत 18 वर्षों में शक्तिशाली गठबंधन सेना के खिलाफ लड़ाई है और उन्हें विस्थापित करने के बावजूद, तालिबान के लिए समय सुनहरा रहा है, यहां तक कि वह अफगानिस्तान के भीतर अपनी राजनीतिक वैधता को लगातार बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी-तालिबान वार्ता टूटी हो और हर बार अमेरिकियों को ही फिर से बातचीत करने के लिए आना पड़ा है। दूसरी ओर श्री डोनाल्ड ट्रम्प के पास सुनहरे समय की कमी रही है।

किसी भी मामले में, हम पहले से कहीं अधिक बार तालिबान द्वारा किए जा रहे विनाशकारी हमलों के साथ अफगानिस्तान में भयंकर युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं।

सामान्य रूप से अस्थिर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए अमेरिकी-अफगान वार्ता के रद्द होने के क्या निहितार्थ हैं और विशेष रूप से इसका भारत पर क्या व्यापक असर पड़ेगा?

## अफगानिस्तान के लिए निहितार्थ

वार्ता से अमेरिकी खींचतान का सीधा संबंध देश में अधिक रक्तपात से संबंधित है। लड़ाई अब आमने-सामने की शुरु हो गयी है (ऐसा नहीं है कि तालिबान इससे पहले बहुत संयमित था) और तालिबान ने पहले ही अमेरिकी सैनिकों के साथ बड़े हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। हालांकि, राष्ट्रपति अशरफ गनी के नेतृत्व में अफगानिस्तान में मौजूदा अशांति, शायद परिणाम से मुंह नहीं फेर सकते हैं। 28 सितंबर को चुनाव के आगे बढ़ने की संभावना है और श्री गनी के पास तालिबान के साथ सत्ता साझा किए बिना, राष्ट्रपति के रूप में जारी रहने का अच्छा मौका है। गनी सरकार इस तथ्य से भी प्रसन्न होगी कि अमेरिकी सैनिकों को देश में ही रहने दिया जाएगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी।

अफगान लोगों के लिए चिंता वाली बात यह है कि क्या तालिबान पहले कि अपेक्षा कुछ बदला है या नहीं। तालिबान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य को उजागर करता है कि उसने कैसे लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बीच अन्य लोगों के उपचार के सवाल पर एक समूह विकसित किया है। लेकिन ये सबसे अच्छा होने का दावा करते हैं और यही वजह है कि तालिबान के साथ वार्ता में इन मुद्दों को भी शामिल किया गया था।

## भारत के लिए इसका क्या मतलब है

एक अच्छी तरह से बातचीत के सौदे के साथ, अफगानिस्तान में तालिबान के उदय का मतलब क्षेत्रीय अनिश्चितता और भू-राजनीतिक पुनरावृत्ति की एक निश्चित मात्रा होगा। मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान की गिनती अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर होती रही है, जो यह मानता है कि यह भारत को रणनीतिक गहराई देता है। अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तानी विजयवाद का मतलब भारत के लिए चिंता का विषय होगा। अब जब तालिबान और अमेरिकी के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तब तक अफगानिस्तान के भीतर आंतरिक रूप से अधिक हिंसा होने की संभावना है। तालिबान के सत्ता में लौटने और विदेशी सैनिकों के हटने पर यह गणना बदल सकती है।

अफगानिस्तान में भारत के लिए सबसे अच्छा मौका अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी पर बातचीत होगी।

अमेरिकी सेनाओं की एक गैर समझौतावादी वापसी भारत के लिए सबसे खराब स्थिति होगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना नहीं है। लेकिन ऐसा होता है तो अफगानिस्तान और आस-पड़ोस में तालिबान के व्यवहार पर बहुत कम जाँच हो पाएगी। यह सामरिक या सामरिक भारतीय विरोधी उपयोगों के लिए तालिबान के तत्वों को नियंत्रित करने की पाकिस्तान की क्षमता को भी बढ़ाएगा।

एक बार अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद, अपने दम पर या सत्ता-साझाकरण व्यवस्था के तहत, अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की संपत्ति और हित दोनों गंभीर दबाव में आ जायेंगे। आज, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी पक्ष के साथ, तालिबान द्वारा भारतीय हितों के खिलाफ जाने की संभावना बहुत अधिक है।

## कश्मीर का सवाल

कई मायनों में कश्मीर इस बात के केंद्र में रहेगा कि अफगानिस्तान में उभरती हुई भूराजनीतिक स्थिति भारत को कैसे प्रभावित करेगी। हालांकि यह सच है कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर कश्मीर में बेरोजगार अफगान लड़ाकों का स्कोर बढ़ा था, लेकिन वर्तमान में कई कारणों से ऐसा होने की संभावना नहीं है, जिसमें शारीरिक बाधाओं और सीमा पर भारी मात्रा में भारतीय सैनिकों का होना शामिल हैं, जिससे मुट्ठी भर तालिबान लड़ाकें लड़ नहीं सकते। हालांकि, अगर अमेरिकी सेनाओं की गैर बातचीत से वापसी होती है, तो यह तालिबान के क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए एक खुला मैदान बन सकता है, जो संभवतः पाकिस्तान की रणनीतिक गणना से प्रभावित हो सकता है। यहां तक कि अगर अमेरिका और तालिबान के बीच एक सौदा होता है, तो यह भी एक तथ्य है कि तालिबान द्वारा अमेरिकियों को अफगानिस्तान से बाहर करने से पाकिस्तान और युवा कश्मीरी जो भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, को बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर पाकिस्तान की मदद से तालिबान द्वारा अफगानिस्तान जैसी महाशक्ति को अफगानिस्तान से ही बाहर धकेला जा सकता है, तो क्या भारत को हराना मुश्किल होगा?

जिस तरह से तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही थी, नई दिल्ली के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस हद तक, ट्रम्प-तालिबान वार्ता का टूटना भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

भारत को अपनी ओर से तालिबान तक पहुंचने की जरूरत है। साथ ही, भारत को उसे पहचानने की नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित में उससे जुड़ने की जरूरत है। वास्तव में, हम इस खेल में पहले से ही बहुत पीछे हो गये हैं और चीनियों, पाकिस्तानियों और यहां तक कि रूसियों का अफगान की तरफ झुकाव से अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत कभी भी तालिबान के उच्च क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगा।

### अमेरिका-अफगानिस्तान युद्ध

#### चर्चा में क्यों?

- अफगानिस्तान में शांति को लेकर अमेरिका और तालिबान में हो रही बातचीत पर पूर्णविराम लगता दिख रहा है।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस आतंकी संगठन के साथ लंबे समय से चल रही बातचीत बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो गई।
- इस बातचीत का अंत अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ होना था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'जहां तक मेरा सवाल है, वो (बातचीत) दफन हो चुकी है।'
- इस फैसले की वजह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान द्वारा किए गए एक हमले को बताया गया है, जिसमें इस हमले में एक अमेरिकी सैनिक सहित 12 लोगों की मौत हो गई थी।
- अमेरिका की ओर से राजनयिक जैलमे खालिलजाद अभी तक तालिबान के साथ नौ दौर की वार्ता कर चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद साल भर से जारी इस वार्ता पर विराम लगता दिखाई दे रहा है।

#### पृष्ठभूमि

- तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में तब हुआ जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान, अफगानिस्तान के परिदृश्य पर 1994 में सामने आया।
- माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिये उभरा जिसमें ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था।
- सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहाँ कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था और मुजाहिदीनों से भी लोग परेशान थे।
- ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ तो अफगान लोगों ने उसका स्वागत किया था।
- प्रारंभ में तालिबान को इसलिये लोकप्रियता मिली, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, अव्यवस्था पर अंकुश लगाकर, अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें।

दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान ने जल्द ही अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया।

धीरे-धीरे तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगने लगे।

2001 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद तालिबान ने विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया।

पाक-अफगान सीमा पर पश्तून इलाके के बारे में तालिबान का कहना था कि वह वहाँ शांति और सुरक्षा का माहौल बनाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया कानून लागू करेगा।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू कार्यवाही जैसे- हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फाँसी, चोरी करने के दोषियों के हाथ-पैर काटना।

दुनिया का ध्यान तालिबान की ओर तब गया जब न्यूयॉर्क में 2001 में हमले किये गए। अफगानिस्तान में तालिबान पर आरोप लगाया गया कि उसने ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को पनाह दी है जिसे न्यूयॉर्क हमलों का दोषी बताया जा रहा था।

#### ट्रंप के फैसले पर संदेह क्यों?

भले ही डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ चल रही वार्ता रोकने के पीछे की वजह काबुल में पिछले सप्ताह हुए हमले को बता रहे हों, लेकिन उनका यह तर्क अधिकांश लोगों के गले नहीं उतर रहा है।

इसकी वजह यह है कि अमेरिका पिछले एक साल से तालिबान से बात कर रहा है और इस दौरान तालिबान के हमलों में कई अमेरिकी सैनिक और राजनयिक भी मारे गए।

एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक तालिबान के हमले में 16 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं।

बीते महीने ही एक हमले में नाटो और अमेरिका के कई अधिकारियों की मौत हुई थी। जानकार सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब साल भर से अमेरिकी सैनिक तालिबान के हमले में मारे जा रहे थे तब अमेरिका ने इस संगठन से बातचीत क्यों नहीं रोकी? ऐसे में अब अचानक एक हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता को रोकना समझ से परे है।

संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. अमेरिकी-तालिबान वार्ता भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके सन्दर्भ में दिए गये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस वार्ता से भारत के सामरिक विरोधी तत्वों को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा।
2. इस वार्ता के बीच अगर सौदा होता है, तो युवा कश्मीरी और पाकिस्तान, जो भारत के खिलाफ हैं, भारत के लिए समस्या बन सकते हैं।
3. भारत को इस समय राष्ट्रीय हित के लिए तालिबान से जुड़ने की जरूरत है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

- (a) 1 और 2                      (b) 2 और 3  
(c) 1 और 3                      (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. The US-Taliban dialogue is crucial to India's security. In this context consider the following statements.

1. This dialogue can not control the strategic and India elements.
2. If deal is concluded this dialogue, then young Kashmiris and Pakistan, who are against India, can become a problem for India.
3. At this time India needs to join the Taliban for the national interest.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 2                      (b) 2 and 3  
(c) 1 and 3                      (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

प्रश्न: अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के भारत के संदर्भ में क्या निहितार्थ हो सकते हैं? अमेरिका के द्वारा शांति वार्ता से पीछे हटने पर भारत के पास क्या बेहतर अवसर मौजूद हैं? चर्चा कीजिए। ( 250 शब्द )

Q. What are the implications of Taliban's retreat in Afghanistan in context of India? What better opportunities do India have when America withdraws from peace talks? Discuss. (250 Words)

नोट : 24 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।